Toppersnotes®
Unleash the topper in you

BPSC

TRE 4.0

बिहार लोक सवो आयोग (BPSC)

भाग - 2

सामान्य अध्ययन – I (भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, राजव्यवस्था, भूगोल, विज्ञान एवं EVS)

SIERRA INNOVATIONS

विषयसूची

S No.	Chapter Title	Page No.
1	1857 का विद्रोह	1
2	भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय	2
3	प्रमुख आन्दोलन	7
4	धर्म एवं समाज सुधार आन्दोलन	8
5	राष्ट्रीय आन्दोलन	10
6	भारतीय आन्दोलन के चरण	12
7	विविध	21
8	संविधान सभा	26
9	प्रस्तावना	30
10	मूल अधिकार	33
11	राष्ट्रपति	43
12	प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्	51
13	संसद	55
14	सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक समीक्षा	69
15	संवैधानिक संशोधन और आधारभूत संरचना का सिद्धांत	75
16	संघवाद	83
17	भारत, आकार और स्थिति	89
18	भारत के भौगोलिक प्रदेश	91
19	भारत का अपवाह तंत्र	107
20	विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण तथ्य	117
21	जीव विज्ञान	123
22	भौतिक शास्त्र	158
23	रसायन शास्त्र	173

विषयसूची

S No.	Chapter Title	Page No.
24	स्थानीय मौसम, जलवायु और जलवायु परिवर्तन	189
25	कृषि एवं फसल	204
26	प्राकृतिक संसाधन	219
27	वन संसाधन एवं वनोन्मूलन	234
28	आपदा प्रबंधन	252
29	पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव	263
30	अंतरिक्ष विज्ञान	272

1 CHAPTER

1857 के विद्रोह

- बैरकपुर में 34वीं इन्फैंट्री के सैनिक मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था।
- 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई।
- 24 मई 1857 को मेरठ छावनी के 90 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया।
- 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में विद्रोह की शुरुआत हुई।
- 20 NI (Native Infantry) और 3 L.C. (Light Cavalry) ने विद्रोह किया था।
- विद्रोही सैनिक दिल्ली की ओर बढ़े और 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को उनका नेता चुना गया।
- **1857 के विद्रोह** के समय भारत के **गवर्नर-जनरल लॉर्ड कैनिंग** थे। उनका शासनकाल इस विद्रोह के दौरान था, जिसे भारतीय इतिहास में **सिपाही विद्रोह** या **पहली स्वतंत्रता संग्राम** के नाम से भी जाना जाता है।

भारतीय नेता (विद्रोह के)	समय (विद्रोह का)	स्थान	विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारी	विद्रोह दबाने का समय
बहादुर शाह ज़फ़र और नाना साहेब, कार्यकारी शहंशाह (नेतृत्व)	11-12 मई, 1857	दिल्ली	जॉन निकोलसन और जॉन हडसन	21 सितम्बर, 1857
नाना साहब और तात्या टोपे	5 जून, 1857	कानपूर	कैप्टन कैम्पबेल	6 जुलाई, 1857
बेगम हजरत महल	4 जून, 1857	लखनऊ	कैप्टन कैम्पबेल	1858
रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे	जून, 1857	ग्वालियर	जनरल ह्यूग रोज़	3 जनवरी, 1858
लियाकत अली	1857	इलाहाबाद, बनारस	कर्नल गिल	1858
कुंवर सिंह	फरवरी, 1857	जगदीशपुर (बिहार)	विलियम टेलर, मेजर विसेंट	1858
खान बहादुर खां	1857	बरेली	कैप्टन शार्ल्स कुप्बेल	1858
मौलवी अहमद हुल्ला	1857	फैजाबाद	जनरल रेनार्ड	1858
अजीमुल्ला खान	1857	फतेहपुर	जनरल रेनार्ड	1858

बंगाल आर्मी में अधिकांश सैनिक अवध के होते थे, इसलिए अवध को 'बंगाल आर्मी की नर्सरी' कहा जाता था।

- **रानी लक्ष्मीबाई** ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था।
- **सिंधिया** ने अंग्रेजों का साथ दिया था और रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में लड़े हुए शहीद हो गईं।
- **हुरोज़** ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था: "भारतीय क्रांतिकारियों में एक मात्र मर्द है।"
- **कैनिन** ने कहा था: "सिंधिया अगर क्रांतिकारी में शामिल हो जाते तो हमें भारत से जाना पड़ता।"

क्रांतिकारियों के योजनाकार:

1. अजीमुल्ला

2. रंगोजी बापू

क्रांति का दिन 31 मई तय किया गया था लेकिन मेरठ में क्रांति 10 मई को ही शुरू हो गई थी |

क्रांतिकारी के प्रतीक:

1. कमल का फूल
2. रोटी

क्रांतिकारी विद्रोह का रूप:

अंग्रेज इतिहासकार		मत
1. लोरेन्स / सिले	-	सैनिक विद्रोह
2. T.R. होम्स	-	सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष,
3. L.E.R. रीज	-	धर्मांधता और ईसाई धर्म के बीच संघर्ष
4. बैज़ामिन डिडरोली	-	राष्ट्रीय विद्रोह
5. आउट्रम - टेलर	-	अंग्रेजो के विरुद्ध हिंदू-मुस्लिम षड्यंत्र

1. **वी. डी. सावरकर** - BOOK -The First War of the Indian Independence और **अशोक मेहता** -BOOK - The Great Rebellion I
2. **रमेश चंद्र मंडल** न पहला, न राष्ट्रीय , न स्वतंत्रता संग्राम (The Sepoy Mutiny & Revolt of 1857)
3. **सुरेंद्रनाथ बनर्जी** - BOOK - 1857
   सैनिक विद्रोह से कुछ अधिक था राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से थोडा कम 1857 की क्रांति का तत्कालीन करण ब्राउन बेस बन्दूको के स्थान पर नई एनफील्ड राइफलो का प्रयोग जिनमे चर्बी लगे कारतूस होते थे। इसमे डलहौड़ी की हड़प नीति भी इसका कारण थी।

2 CHAPTER भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय

1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया |

गवर्नर जनरल का क्रम:

1. वॉरेन हैस्टिंग्स (1772-85)
2. लॉर्ड कॉर्नवालिस (1785-93)
3. जॉन शोर (1793-98)
4. वेलेजली (1798-1805)
5. जॉर्ज बार्लो(1805)
6. लॉर्ड मिन्टों (1805-07)
7. लॉर्ड हैस्टिंग्स (1807-13)
8. जॉन एडम्स (1823)
9. लॉर्ड एमहर्स्ट (1823-28)

1. वॉरेन हैस्टिंग्स (1772-85)

- 1772 में इसे बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया।
- 1773 में "रेग्युलेटिंग एक्ट" के तहत इन्होंने बंगाल के गवर्नर जनरल को बढ़ावा दिया।
- 1772 में "कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स" के तहत इसने बंगाल से द्वैध शासन समाप्त किया।
- 1784 में पिट्स इण्डिया एक्ट के विरोध में इसने इस्तीफा दे दिया।
- 1780 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। (1773 के रेग्युलेंटिग एक्ट के अनुसार)
- इसमे अंग्रेजी कानून ही लागू होते थे तथा इसका क्षेत्राधिकार केवल कलकत्ता क्षेत्र ही था |
- यदि दोनो पक्ष सहमत हो तो बाहर का मामला भी कलकत्ता सुप्रीमकोर्ट में सुना जा सकता है |
- **प्रथम न्यायाधीश (कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट)** - एलिजा इम्पे (मुख्य न्यायाधीश) |

2. लॉर्ड कॉर्नवालिस (1786-1793)

- अपने न्यायिक सुधारों के तहत इन्होंने सर्वप्रथम जिले की समस्त शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी।
- कॉर्नवालिस ने भारत में सर्वप्रथम "कानून की विशिष्टता" का नियम लागू किया।
- 1793 में कॉर्नवालिस ने "कॉर्नवालिस कोड" का निर्माण किया जो "शक्तियों के पृथक्करण" के सिद्धांत पर आधारित था।
- कॉर्नवालिस को "पुलिस सुधारों का जनक" भी कहा जाता है।
- कॉर्नवालिस की मृत्यु उत्तरप्रदेश के गाजीपुर जिले में हुई ।
- इसी के शासन में 'बोर्ड ऑफ रेवेन्यू' कि स्थापना हुई थी ।
- कॉर्नवालिस की मृत्यु उत्तरप्रदेश के गाजीपुर जिले में हुई ।
- इसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया ।
- कॉर्नवालिस को भारत में "नागरिक सेवा का जनक" माना जाता है।

3. सर जॉन शोर

- अहस्तक्षेप नीति एवं खारदा का युद्ध सर जॉन शोर के काल की महत्वपूर्ण घटना थी ।
- खारदा का युद्ध 1795 ई. में मराठों एवं निजाम के बीच लड़ा गया ।

4. लॉर्ड वेलेजली (1798-1805)

- यह अपनी सहायक संधि के कारण प्रसिद्ध हुआ ।
- इसके समय "चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध" (1799) में हुआ।
- नागरिक सेवाओं के प्रशिक्षण हेतु इसने 1800 में कलकत्ता में "फोर्ट विलियम कॉलेज" की स्थापना की ।
- इसे "बंगाल का शेर" उपनाम से भी जाना जाता है ।
- 1801 में इसके समय मद्रास प्रेसीडेन्सी का सृजन किया गया ।
- 1802 में पेशवा बाजीराव II के साथ बेसीन की संधि की।

5. जॉर्ज बार्लो(1805)

- 1806 वैल्लोर विद्रोह (मद्रास)
  कारण : अंग्रेजो द्वारा धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग बन्द कर दिया था। उस समय मद्रास का गर्वनर विलियम बैन्टिक था। इसने प्रेस पर प्रतिबन्ध को विद्रोह का कारण बताया था ।
- होल्डर के साथ सहायक संधि (राज पुरघाट की संधि)

6. लार्ड मिन्टों (1807-13)

- 1809 अमृतसर की संधि
- इसी के कार्यकाल में चार्टर एक्ट 1813 पारित हुआ था।

7. लॉर्ड हेस्टिंग्स (1813-23)

- बिना बराबरी के स्तर पर मुगल बादशाह से मिलने से मना कर दिया ।
- मद्रास में टॉम्स मुनरो के द्वारा रैयतवाडी की व्यवस्था लागू की गई ।

प्रथम आंग्ल - नेपाल युद्ध : (1814-16)

- संगौली की सन्धि द्वारा युद्ध समाप्त हुआ ।

8. जॉन एडम्स (1823)

- इसने प्रेस पर प्रतिबन्ध लगा दिया था ।
- राजा राम मोहनराय के 'मिरातुल अखबार' को बन्द कर दिया था

9. लॉर्ड एमहर्स्ट (1823-28)

- यह पहला गवर्नर जनरल जो मुगल बादशाह से बराबरी के स्तर पर मिला ।

प्रथम आंग्ल - बर्मा युद्ध : (1824-26)

- 'यान्दबू की सन्धि' द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ

भारत के गवर्नर जनरल

- 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गर्वनर जनरल बना दिया गया ।
- 'विलियम बैटिक' भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था

गवर्नर का क्रम : (भारत के गवर्नर जनरल)

1. विलियम बैटिक (1828-35)
2. चार्ल्स मेटकॉफ (1835-36)
3. लॉर्ड ऑकलैण्ड (1836-42)
4. लॉर्ड एलनबबरो (1842-44)
5. लॉर्ड हार्डिंग प्रथम (1844-48)
6. लॉर्ड डलहौजी (1848-56)

1. विलियम बैन्टिक (1828-35)

- भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में आया था लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया ।
- 1829 में धारा 17 के तहत सती प्रथा पर रोक लगा दी यह रोक राजाराममोहनराय के प्रयासों से लगी थी
- विलियम बैन्टिक ने ठग प्रथा का उन्मूलन किया था "कर्नल सलीमैन" के नेतृत्व में इसका उन्मूलन किया था।
- 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की।
- 1835 में मैकाले स्मरण पत्र जारी किया गया जिसमें शिक्षा हेतु विप्रवेशन / निस्पदन / टपक / छनन / बूंद-बूंद सिद्धांत दिया। इसके अंतर्गत भारतीय उच्च वर्ग को अंग्रेजी में शिक्षा दी जाएगी। जो टपक-टपक कर जनसाधारण तक पहुंच जाएगी ।

2. चार्ल्स मैटकॉफ : (1835-36)

- चार्ल्स मैटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है।
- इसने 1818 में राजस्थान की रियासतों के साथ सन्धि करने के लिए अंग्रेजो की तरफ से प्रतिनिधि था ।

3. लॉर्ड ऑकलैण्ड : (1836-42)

- 1839 में इसने कोलकत्ता से दिल्ली तक ग्राण्ड ट्रक रोड का मरम्मत करवाया ।

प्रथम आंग्ल -अफगान युद्ध : (1839-42)

- कारण : अफगानिस्तान का राजा दोस्त मोहम्मद रूस से दोस्ती कर रहा था ।
- कलकत्ता से दिल्ली के बीच जी.टी. रोड का पुनर्निमाण करवाता है।

4. लॉर्ड एलनबरीः (1842-44)

- 1843 में सिन्ध का विलय किया गया ।(यह विलय नेपियर के नेतृत्व में हुआ था।)
- 1843 में दास प्रथा (धारा-5) पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था (यह घोषणा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत की गई थी ।)
- इसका कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है।

5. लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम (1844-48)

प्रथम आंग्ल सिख युद्ध (1845-46)

- औडिशा में खोखोड़ो के बीच प्रचलित नर बलि कि प्रथा को समाप्त कर दिया ।

6. लॉर्ड डलहौजी (1848-56)

- डलहौजी आधुनिक भारत के मानचित्र का निर्माता था ।
- डलहौजी ने भारतीय रियासतों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था ।
- रेलवे माईनुट ने 1853 में बंबई से थाणे तक रेल का परिचालन प्रारंभ किया।
- शिमला की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया ।

युद्ध द्वारा किये गये विलय

1. पंजाब (1849)
2. विभाजन (1850)
3. लाहौर बर्मा व पीगू (1852)

शान्तिपूर्ण तरीके से किये गये विलय :

गोद निषेध नीति / व्ययगत / एचडीपी नीति

i. 1848 सतारा
ii. 1849 जैतपुर / संभलपुर
iii. 1850 बघाट
iv. 1852 उदेपुर (एम.पी)
v. 1853 झाँसी
vi. 1854 नागपुर
vii.1855 करौली

डलहौजी के सुधार

- 1852 में भारत में तार सेवा शुरू की थी। तार विभाग का प्रमुख ओ शेघने सी था |
- 1853 में भारत में रेल सेवा शुरू की ।
- पहली रेल बॉम्बे से थाने के बीच चलाई गई थी । इंजन - फेयरी क्विन
- 1854 में डाक सेवा शुरू की थी । (डाक टिकट 2 पैसे का होता था) डलहौजी ने सैनिकों के लिए भी डाकटिकट अनिवार्य कर दिया था ।

- 1854 में सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) बनाया गया ।
- 1854 में शिक्षा में सुधार किये थे ।

  ये सुधार चार्ल्स वुड के नेतृत्व में किये थे इसलिए इन्हें वुड डिस्पैच कहा जाता है।

  चार्ल्स वुड बॉर्ड ऑफ कन्ट्रोल का अध्यक्ष था ।

भारत के वायसराय

1858 के भारत परिषद् अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की वायसराय भी बना दिया गया ।

लॉर्ड केनिंग भारत का प्रथम वायसराय था ।

(1) लॉर्ड कैनिंग (1856-62)

(2) लॉर्ड एल्गिन प्रथम (1862-63)

(3) जॉन लॉरेन्स (1863-69)

(4) लॉर्ड मेयो (1869-72)

(5) लॉर्ड नॉर्थबुक (1872-76)

(6) लॉर्ड लिटन (1876-80)

(7) लॉर्ड रिपन (1880-84)

(8) लॉर्ड डफरिन (1884-88)

(9) लॉर्ड लैंड्सडाउन (1888-94)

(10) लॉर्ड एल्गिन -द्वितीय (1894-99)

(11) लॉर्ड कर्जन (1899-1905)

1. लॉर्ड कैनिंग (1856-62)

- यह कम्पनी का अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय था।
- इसके समय ही युरोपीय सेना के द्वारा श्वेत विद्रोह हुआ था ।
- 1856 में विधवा पुर्नविवाह अधिनियम पारित हुआ (धारा 15) ईश्वर चन्द्र विद्यासागर के प्रयासी से यह कानून बनाया गया था
- 1857 की क्रान्ति के समय गवर्नर जनरल था ।
- 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे व मदास में विश्वविद्यालय बनाये गयें । (लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर)
- 1861 में इडियन हाइकोर्ट एक्ट पारित हुआ तथा कालान्तर में बॉम्बे, मदास में हाइकोर्ट की स्थापना की गई ।
  - सी.पी.सी - सिविल प्रक्रिया न्यायालय
  - सी.आर.पी.सी - दंड प्रक्रिया न्यायालय
  - I.P.C को अलग किया - भारतीय दंड न्यायालय
- 1860 में जेम्स विल्सन के नेतृत्व में आर्थिक सुधार कियें।
- पहली बार बजट पेश किया गया ।
- (500 रूपये से अधिक आय पर 1% कर लगाया जाता था ।)
- विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया था ।

2. जॉन लॉरेन्स (1863-69)

- केम्पबेल की अध्यक्षता में अकाल आयोग गठन किया गया था ।
- 1865 में कलकत्ता, मुम्बई, मद्रास के न्यायलयों कि स्थापना की ।
- भारत से ब्रिटेन के बीच समुद्री टेलीग्राम (तार) सेवा शुरू की ।
- अफगानिस्तान के प्रति इसने कुशल अकर्मण्यता की नीति अपनाई । (कुशल अकर्मण्यता शब्द का प्रयोग J. W. S. वाईली ने किया था ।

3. लॉर्ड मेयो (1869-1872)

- मेयो ने भारत में वित्तीय विकेन्द्रीकरण की नीति की शुरूआत की । इसने बजट घाटे को कम किया
- कठियावाड एवं अलवर को इसने भ्रष्टाचार एवं कुशासन के आधार पर दण्डित किया ।
- इसने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की ।
- 1872 में इसने एक कृषि विभाग की स्थापना की
- मेयो के शासनकाल में 1872 ई. में सर्वप्रथम प्रायोगिक जनगणना करवाई गई ।

4. लार्ड नार्थबुक (1872-76)

- कूका आन्दोलन का दमन किया था ।
- ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 पारित कर बाल विवाह पर प्रतिबंध ।
- लॉर्ड नार्थबुक मुक्त व्यापार का समर्थक था।

5. लॉर्ड लिटन (1876-80)

- 'ओवेन मेरेडिथ' नाम से साहित्य लिखता था ।
- 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया तथा महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिन्द की उपाधि दी थी ।
- रिचर्ड स्ट्रेची के नेतृत्व में अकाल आयोग की स्थापना की गई।
- **वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट (1878):** (वर्नाक्यूलर - स्थानीय भाषा)
  - देशी/स्थानीय भाषा के समाचार पत्र सरकार के खिलाफ लिखने पर जब्त कर लिये जायेंगे ।
- लिटन ने अलीगढ में एक मुस्लिम -ऐग्लो प्राच्य महाविद्यालय कि स्थापना कि तथा सिविल सेवा कि उम्र घटाकर 21 से 19 कर दिया ।
- इसे गैगिंग एक्ट (Gagging Act) (मुँह बन्द रखना) भी कहा जाता है।

वैधानिक जनपद सेवा (1879)

- लिटन ICS में भारतीयों का प्रवेश रोकना चाहता था इसलिए उसने नई सेवा शुरू की। इनका पद तथा वेतन ICS से कम होता था ।

- इनकी संख्या ICS की ⅙ होती थी ।
- ICS की अधिकतम आयु 19 वर्ष कर दी गई ।
- सत्येन्द्र नाथ टैगोर प्रथम भारतीय ICS थें ।
- 1886 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई
- 1919 के भारत परिषद अधिनियम में केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई ।
- 1935 के भारत शासन अधिनियम में संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। जो बाद में UPSC बन गया।

6. लॉर्ड रिपन (1880-84)

- यह अच्छी प्रवृति का व्यक्ति था ।
- 1881 में प्रथम नियमित जनगणना करवाई ।
- प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 लागू हुआ ।
- 1881 में रिपन मैसूर वापस लौट गया था ।
- 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बंद कर दिया था ।
- 1882 में भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरूआत की गई । (नगरपालिका, नगरबोर्ड आदि बनाये गये)
- 1882 में भारत में शिक्षा सुधार किये गयें। इसके लिए 'हन्टर आयोग' बनाया गया था । प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में सुधार किये जायेंगें ।
- इलबर्ट बिल विवाद (1883-84) के कारण इन्हे कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र देना पडा । इस विवाद की श्वेत विद्रोह कहा जाता है।

इल्बर्ट बिल विवाद : (1883)

- कोई भी भारतीय न्यायाधीश फौजदारी मामले में अंग्रेज मुजरिम को नहीं सुन सकता था । इसमें P.C. इल्बर्ट विधि सदस्य (Legal Member) था ।
- मिस्त्र में भारतीय सेना भेजने के सवाल पर रिपन ने इस्तीफा दे दिया था ।
- फलोरेन्स नाइटिंगेल ने रिपन की भारतीयों का उद्धारक कहा था ।

7. लॉर्ड डफरिन (1884-88)

- 28 दिसम्बर 1885 की कांग्रेस की स्थापना हुई थी । (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस)
- इसके समय (1885-88) तृतीय आंग्ल-वर्मा युद्ध हुआ वर्मा को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया ।

8. लॉर्ड लैड्सडाउन (1888-94)

- भारत - अफगानिस्तान के बीच डुरण्ड लाइन खिंची गई थी ।
- 1891 - दूसरा कारखाना अधिनियम लागू हुआ ।
- इसके तहत महिलाओं से 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम पर प्रतिबंध एवं सप्ताह में एक दिन अवकाश की व्यवस्था की

9. लॉर्ड कर्जन (1899-1905)

- तिलक ने कहा था "कैसा दुर्भाग्य है अकाल, प्लेग, और कर्जन तीनों भारत एक साथ आयें ।"
- एंटनी मैक्डॉनाल्ड - अकाल आयोग
- सिंचाई आयोग - स्कॉट मानक्रिफ
- पुलिस आयोग - एंड्रयू फेजर
- विश्वविद्यालय अधिनियम (1904) लागू हुआ ।
- रॉबर्टसन के नेतृत्व में भारत में रेलवे सुधार किये थें ।
- सबसे अधिक रेलवे का विकास कर्जन के समय में हुआ था ।
- कलकत्ता नगर निगम अधिनियम (1899)
- कर्जन ने नगर निगम में सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी ।
- भारतीय टंकण एवं पत्र मुदा अधिनियम (1899)
- पौण्ड को भारत में वैध किया गया तथा 1 पाउण्ड = 15 रूपये होगा
- रूपये को स्वर्ण प्रमाप पर रखा गया था ।
- सहकारी समिति अधिनियम (1904)
- किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए
- प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम (1904)
- 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई।
- 1903 में यंगहसबैंड के नेतृत्व में तिब्बत पर आक्रमण कर दिया । चुंबी घाटी पर 75 वर्षों के लिए अधिकार कर लिया ।
- 1905 में बंगाल विभाजन किया ।

बंगाल विभाजन (1905)

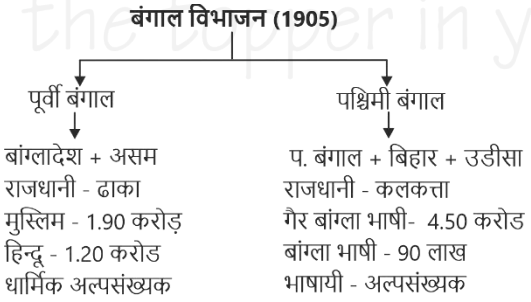

कर्जन ने विभाजन का कारण प्रशासनिक अव्यवस्था बताया लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य बंगाली हिन्दुओं में बढ़ती राष्ट्रवादी भावनाओं की कुचलना था ।

कर्जन के सैनिक सुधार

1. सेनापति किचनर ने सैनिको के लिए किचनर टेस्ट शुरू किया ।
2. क्वेटा (पाक) में सैनिक अधिकारियों के मिलिट्री प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई ।

   सैनिक सदस्य की नियुक्ति पर कर्जन तथा किचनर में विवाद हो गया तथा कर्जन ने इस्तीफा दे दिया ।

10. लार्ड चेम्सफोर्ड

- कांग्रेस के लखनऊ अधीवेशन 1916 से कांग्रेस का एकीकरण एवं मुस्लीम लीग से समझौता
- 1919 के संवैधानिक सुधार अधीनियम द्वारा प्रान्तों में द्वैध शासन लागू।
- खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था।

11. लार्ड इरविन

- 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति
- 1929 में शारदा एक्ट पारित
- 1929 में लाला लाजपतराय की मृत्यु एवं असेम्बली में बम फेंका गया।
- 12 नवम्बर 1930 की लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन

12. लार्ड बेवेल

- 1945 में शिमला समझौता
- 12 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया
- इनके समय में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी।

13. लार्ड माउण्टबेटेन

- मार्च 1947 की भारत का गवर्नर जनरल लार्ड माउण्ट बेटेन को बनाया गया।
- इनके समय 3 जून 1947 की भारत विभाजन की घोषण की गई।
- स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल

14. सी. राज गोपालचारी

- स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल
- 26 जनवरी 1950 की संविधान लागू किये जाने के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

3 CHAPTER प्रमुख आन्दोलन

राज्य	आंदोलन / विद्रोह	संबंधित नेता / नेतृत्व	वर्ष
बिहार	सन्यासी विद्रोह	केना सरकार, दिरबीर नारायण	1763-1800 ई.
	संथाल विद्रोह	सिद्धू-कान्हू	1855-57 ई.
	मुंडा विद्रोह	बिरसा मुंडा	1899-1900 ई.
	ताना भगत आंदोलन	जतरा भगत और तुरिया जगत	1914 ई.
बंगाल (अब बंगाल + झारखंड)	फकीर विद्रोह	मजनुशाह, चिराग अली	1776-77 ई.
	चुआर विद्रोह	दुर्जन सिंह	1798 ई.
	नील आंदोलन	दिगम्बर	1859-60 ई.
	पाबना विद्रोह	ईशान चंद्र राय, शम्भुपाल	1873-76 ई.
	तेभागा आंदोलन	कंपाराम सिंह, भवन सिंह	1946 ई.
झारखंड	कोल विद्रोह	नारायण सिंह	1831-32 ई.
असम	पागलपंथी विद्रोह	टीपू शाह	1825-27 ई.
	अहोम विद्रोह	गोमधर कुंवर	1828 ई.
	खासी विद्रोह	तीरथ सिंह	1829 - 1833 ई.
तमिलनाडु	पॉलीगर विद्रोह	वीर पी. काट्टाबोम्मन	1799-1801 ई.
केरल	वेलुथम्पी विद्रोह	वेलू थंपि	1808-09 ई.
	मोपला विद्रोह	अली मुदालियार	1920-22 ई.
महाराष्ट्र	भील विद्रोह	सेवाराम	1825-31 ई.
	दक्कन किसान विद्रोह	-	1874-75 ई.
उत्तर प्रदेश	वहाबी आंदोलन	सैयद अहमद बरेलवी	1831 ई.
उड़ीसा	पाइका विद्रोह	बक्शी जगबन्धु	1817-1825 ई.
पंजाब	कूका आंदोलन	और बाबा बालक सिंह भगत जवाहरमल	1872 ई. लगभग
आंध्र प्रदेश	रामपा विद्रोह	अल्लूरी सीताराम राजू	1879-1922 ई.
	तेलंगाना आंदोलन	-	1946-51 ई.

नोट : भूदान आंदोलन 1951 में **विनोबा भावे** द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य भूमि मालिकों को प्रेरित करना था ताकि वे अपनी ज़मीन का एक हिस्सा स्वेच्छा से भूमिहीन गरीबों को दे सकें। यह आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में भूमि वितरण की समस्याओं को हल करने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था।

4 CHAPTER धर्म एवं समाज सुधार आन्दोलन

19वीं सदी के प्रारंभ में जब भारत में सामाजिक कुरीतियाँ और धार्मिक अंधविश्वास प्रचलित थे, तब राजा राम मोहन राय ने तर्क, विज्ञान और सामाजिक सुधार का मार्ग अपनाया। **भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत** और **आधुनिक भारत के जनक** माने जाते हैं।

राजा राम मोहन राय

राजा राम मोहन राय की उपाधियाँ:

- आधुनिक भारत का पिता
- भारतीय पुनर्जागरण का जनक
- अतीत और भविष्य के बीच सेतु

राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रमुख संगठन:

1. **आत्मीय सभा** – 1815
2. **हिंदू कॉलेज (कोलकाता)** – 1817 (डेविड हेयर के साथ मिलकर)
3. **वेदांत कॉलेज** – 1825
4. **ब्रिटिश यूनिटेरियन एसोसिएशन** – (सहयोगी संस्था)
5. **ब्रह्म समाज** – 1828

राजा राम मोहन राय की प्रमुख कृतियाँ (पुस्तकें):

1. **तुहफ़त-उल-मुवाहिदीन** or एकेश्वरवादियों के उपहार or **Gift to Monotheists**
2. **हिंदू उत्तराधिकार के नियम**
3. **Precepts of Jesus**

राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित पत्रिकाएँ:

1. **मिरात-उल-अखबार** (फारसी में)
2. **संवाद कौमुदी** (बंगाली में)
3. **Brahmanical Magazine** (अंग्रेजी में)

अन्य प्रमुख सहयोगी और सुधारक:

ताराचंद चक्रवती

द्वारकानाथ टैगोर

- 1843 में **देवेन्द्रनाथ टैगोर ने** ब्रह्म समाज की **नेतृत्व संभाला**
- इन्होने 1839 में **तत्वबोधिनी सभा** की स्थापना की
- **तत्वबोधिनी नामक पत्रिका** शुरू की
- संपादक - **अक्षय कुमार दत्त**
- **देवेन्द्रनाथ टैगोर ने केशवचंद्र सेन** को ब्रह्म समाज का **आचार्य** नियुक्त किया
- **1865** में केशवचंद्र सेन को ब्रह्म समाज से **निकाल दिया गया तथा** बाद में इन्होंने **भारतीय ब्रह्म समाज** की स्थापना की
- अत:बाद में देवेन्द्र नाथ टैगोर का ब्रह्म समाज , **आदि ब्रह्म समाज** कहलाया | (देवेन्द्रनाथ के नेतृत्व में)
- 1872 में **Native Marriage Act** (इसको भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम भी कहा जाता है |)पारित हुआ तथा विवाह की न्यूनतम आयु: लड़कियों के लिए 14 वर्ष, लड़कों के लिए 18 वर्ष तय की गई |
- केशवचंद्र ने अपनी नाबालिग पुत्री का विवाह **कूच बिहार** के राजा से कर दी थी इसलिए उनके समर्थकों ने अलग होकर 1878 **में "साधारण ब्रह्म समाज"** की स्थापना की |

साधारण ब्रह्म समाज

प्रमुख समर्थक:

- **आनंद मोहन बोस**
- **सुरेन्द्रनाथ बनर्जी**
- **द्वारिकानाथ गांगुली**

केशवचंद्र सेन द्वारा स्थापित संस्थाएँ/पत्रिकाएँ:

1. **मैत्री सेन** (सामाजिक सुधार संगठन)
2. **Tabernacle of New Dispensation** (नवधर्म उपदेश स्थल)
3. **इंडियन रिफार्म एसोसिएशन**
4. **Indian Mirror** (उनकी प्रमुख पत्रिका)

प्रार्थना समाज (1867)

स्थान: महाराष्ट्र **स्थापक:**

1. जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे
2. आत्माराम पांडुरंग
3. आर. जी. भंडारकर
4. चंद्रावाकर

महादेव गोविंद रानाडे

- गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु
- इन्हें **"महाराष्ट्र का सुकरात" भी कहा जाता है |**

उनके प्रमुख संगठन:

1. **विधवा विवाह संघ** – 1867
2. **पूना सार्वजनिक सभा** – 1871
3. **दक्कन एजुकेशनल सोसायटी** – 1884
   - बाद में **फर्ग्यूसन कॉलेज**, पुणे बना
4. **नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस** – 1887

नोट: तिलक, गोखले, और आगरकर जैसे नेता फर्ग्यूसन कॉलेज से जुड़े हुए थे।

आर्य समाज (1875)

- **संस्थापक:** स्वामी दयानंद सरस्वती
- **स्थापना:** 1875, मुंबई
- **जन्म :** 1824 , गुजरात के काठियावाड़ में
- **मुख्य उद्देश्य:** वैदिक धर्म की शुद्धता की पुनर्स्थापना और सामाजिक सुधार
- स्वामी जी ने झूठे धर्मो का खंडन करने के लिए **"पाखंड खंडनी पताका"** लहराई, तथा इन्होने "वेदों की ओर लौटो" का नर दिया |
- **स्वामी जी ने गोधन की रक्षा हेतु** – "गोरक्षिणी सभा" की स्थापना की तथा **"गौकरणानिधि"** नामक पुस्तक की रचना

स्वामी दयानंद सरस्वती की रचनाएँ:

1. सत्यार्थ प्रकाश
2. पाखंड खंडन
3. वेद भाष्य भूमिका
4. ऋग्वेद भाष्य
5. अद्वैतमत का खंडन
6. पंचमहायज्ञ विधि

रामकृष्ण मिशन (1897)

स्वमी विवेकानन्द जी ने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में की |

वहाबी आंदोलन

- **प्रारंभ:** अरब में अब्दुल वहाब द्वारा
- **भारत में:** सैयद अहमद बरेलवी द्वारा प्रचारित
- **उद्देश्य: दारुल-हरब** को **दारुल-इस्लाम** में बदलना
- शुरुआत पंजाब में सिखों के विरुद्ध था
- पंजाब के विलय होने के बाद अंग्रेजो के खिलाफ हो गया |
- यह हिंसक व संप्रदायिक आंदोलन था
- कालांतर में पूर्वी भारत इसका मुख्य केंद्र हो गया
    - प्रमुख नेता: हाजी करामात अली और शरीयत उल्ला खां

थियोसोफिकल सोसाइटी

- **स्थापना:** 1875, न्यूयॉर्क
- **भारत में मुख्यालय:** मद्रास (चेन्नई)
- **एनी बेसेंट** 1889 में इस सोसाइटी की सदस्य बनी तथा 1907 में अध्यक्ष बनीं |

अलीगढ़ आंदोलन

- **यह आंदोलन सर सैयद अहमद ख़ाँ ने चलाया था।** इन्होंने मुसलमानों में आधुनिकीकरण लाने का प्रयास किया इसलिए अंग्रेज़ी शिक्षा का समर्थन किया और अंग्रेज़ी सरकार के साथ सहयोग किया।
- इन्होंने क़ुरान की वैज्ञानिक व्याख्या की।
- **पीर-मुरीदी** प्रथा का विरोध किया।
- **बाइबिल** पर टीका लिखी।

प्रमुख संगठन:

1. **1863** – **मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी**
2. **1864** – साइंटिफिक सोसाइटी
3. **1875** – मुहम्मडन एंग्लो–ओरिएंटल कॉलेज
    - यही कॉलेज **1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय** (AMU) बना
4. **1888** – देशभक्त एसोसिएशन
    - बनारस के राजा शिवप्रसाद के साथ मिलकर बनाया |
    - यह कांग्रेस **विरोधी संस्था थी |**

प्रमुख पत्र/लेख:

1. **तहज़ीब-उल-अख़लाक़**
2. **राष्ट्रभक्त मुसलमान** (Deshbhakt Musalman)

अहमदिया आंदोलन

- **स्थापना:** 1889
- **स्थान:** क़ादियाँ, गुरदासपुर (पंजाब)
- **संस्थापक:** मिर्ज़ा गुलाम अहमद

रहनुमाई मजदेसन / रहनुमा-ए- माजदा - ए - सभा

- **स्थापना:** 1851
- **स्थान:** मुंबई
- **संस्थापक:** नौरोजी फरदीन जी, दादाभाई नौरोजी, आर. के. कामा, एस.एस. बंगाली
- इस संस्था ने रास्त गोफ्तार (सत्यवादी) नामक पत्रिका का प्रकाशन किया

परमहंस मंडली

स्थान: महाराष्ट्र

संस्थापक: गोपाल हरिदेव मुख (प्रसिद्ध नाम – **लोकहितवादी**)

यह एक सामाजिक सुधार संगठन था जिसे 1840 में **विनोबा भावे** और उनके सहयोगियों द्वारा स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य समाज में सुधार लाना, अछूतों के अधिकारों की रक्षा करना और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच एकता को बढ़ावा देना था।

5 CHAPTER राष्ट्रीय आन्दोलन

28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसी दिन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की **औपचारिक शुरुआत** के रूप में माना जाता है।

कांग्रेस की स्थापना से पूर्व के प्रमुख राजनीतिक संगठन

1. **बंगाल ज़मींदार सभा – 1838**
   - भारत का पहला राजनीतिक संगठन
   - संस्थापक: राधाकांत देव और द्वारकानाथ टैगोर
2. **बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन – 1843**
   - संस्थापक: द्वारकानाथ टैगोर
3. **ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन – 1851**
   - द्वारकानाथ टैगोर व राधाकांत देव के प्रयास से गठित
4. **इंडियन लीग – 1875**
   - संस्थापक: शिशिर कुमार घोष
5. **इंडियन एसोसिएशन – 1876**
   - संस्थापक: सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस
   - लिटन ने ICS की अधिकतम आयु 19 वर्ष कर दी थी इस कारण सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने आन्दोलन शुरू किया|
6. **नेशनल कॉन्फ्रेंस – 1883**
   - संस्थापक: सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस

मद्रास क्षेत्र

1. **मद्रास नेटिव एसोसिएशन – 1852**
   - इस संगठन ने 1857 की क्रांति की आलोचना की इसलिए यह लोगों में अलोकप्रिय हो गया था|
2. **मद्रास महाजन सभा – 1884**
   - संस्थापक: वी. राघवाचार्य, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चारलू

बॉम्बे

बॉम्बे एसोसिएशन – 1852

- बाद में नाम बदलकर "बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन" रखा गया (1885)
- प्रमुख नेता: बदरुद्दीन तैय्यबजी, फिरोजशाह मेहता

ईस्ट इंडिया एसोसिएशन – 1866

- संस्थापक: दादाभाई नौरोजी
- स्थान: लंदन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

- 1884 में थियोसॉफिकल सोसायटी का अधिवेशन अडियार (आधुनिक चेन्नई) में हुआ
- ए. ओ. ह्यूम ने एक अखिल भारतीय संगठन बनाने का प्रस्ताव दिया
- इस संगठन का नाम **इंडियन नेशनल यूनियन** रखा गया| इसका पहला सम्मेलन पूना में होना था लेकिन वहां पर प्लेग फ़ैल जाने के कारण इनका पहला सम्मेलन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ| दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस** रखा गया| (कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका सी लिया गया)
- कांग्रेस के पहले अध्यक्ष: **डब्ल्यू. सी. बनर्जी (व्योमेश चंद्र बनर्जी)**
- कांग्रेस का अर्थ: लोगों का समूह (A Group of People)

कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन

सत्र संख्या	वर्ष (तिथि)	स्थान	अध्यक्ष	अधिवेशन का विवरण (संक्षिप्त)
प्रथम सत्र	1885 (28-30 दिसंबर)	बंबई	व्योमेश चंद्र बनर्जी	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, जिसमें राजनीतिक विचार-विमर्श और राष्ट्रीय एकता पर चर्चा हुई।
दूसरा सत्र	1886 (27-30 दिसंबर)	कलकत्ता	दादाभाई नौरोजी	औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ भारतीयों के अधिकारों की मांग पर जोर, स्वतंत्रता के विचारों का प्रारंभिक प्रसार।
तीसरा सत्र	1887 (27-30 दिसंबर)	मद्रास	बदरुद्दीन तैयबजी	स्वदेशी विचारों की शुरुआत, भारतीय स्वशासन की मांग को लेकर प्रारंभिक चर्चा।
चौथा सत्र	1888 (26-29 दिसंबर)	इलाहाबाद	जॉर्ज यूल	प्रशासनिक सुधारों और भारतीयों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की गई।
5वां सत्र	1889 (26-28 दिसंबर)	बंबई	सर विलियम वेडरबर्न	कृषि, शिक्षा और आर्थिक सुधारों पर चर्चा; भारतीयों के लिए शिक्षा में बढ़ावा।

6वां सत्र	1890 (26-30 दिसंबर)	कलकत्ता	फिरोजशाह मेहता	भारतीय युवाओं के लिए शिक्षा और प्रशासनिक नौकरियों में अधिक अवसरों की मांग।
7वां सत्र	1891 (28-30 दिसंबर)	नागपुर	पी. आनंद चार्लु	किसान एवं मजदूर वर्ग की समस्याओं पर चर्चा, सामाजिक सुधारों की दिशा में पहल।
8वां सत्र	1892 (28-30 दिसंबर)	इलाहाबाद	व्योमेश चंद्र बनर्जी	राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने के प्रयास, भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिक प्रतिनिधित्व का आग्रह।
9वां सत्र	1893 (27-30 दिसंबर)	लाहौर	दादाभाई नौरोजी	ब्रिटिश शासन की आलोचना, भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन की मांग, सांस्कृतिक एकता पर बल।
10वां सत्र	1894 (26-29 दिसंबर)	मद्रास	अल्फ्रेड वेब	भारतीय उद्योगों और व्यापार को प्रोत्साहित करने पर चर्चा, आर्थिक स्वराज की शुरुआत।
11वां सत्र	1895 (27-30 दिसंबर)	पुणे	सुरेन्द्रनाथ बनर्जी	भारतीय भाषाओं और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए पहल, सामाजिक सुधारों की चर्चा।
12वां सत्र	1896 (28-31 दिसंबर)	कलकत्ता	रहीमतुल्लाह एम. सयानी	सामाजिक एकता और विभिन्न समुदायों के बीच सौहार्द्र बढ़ाने पर जोर।
13वां सत्र	1897 (27-29 दिसंबर)	अमरावती	सी.शंकरन नायर	ग्रामीण विकास और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियाँ बनाई गईं।
14वां सत्र	1898 (29-31 दिसंबर)	मद्रास	आनंद मोहन बोस	भारतीय इतिहास और संस्कृति को संरक्षित करने की जरूरत पर चर्चा।
15वां सत्र	1899 (27-29 दिसंबर)	लखनऊ	रोमेश चंद्र दत्त	भारतीय किसानों और मजदूरों की समस्याओं पर फोकस, सामाजिक न्याय पर जोर।
16वां सत्र	1900 (27-29 दिसंबर)	लाहौर	एन.जी.चंदावरकर	भारतीय प्रशासनिक सेवा में सुधार की मांग, भारतीय युवाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करने पर बल।
17वां सत्र	1901 (26-28 दिसंबर)	कलकत्ता	दिनशॉ एडुलजी वाचा	स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत के लिए रणनीतियाँ, राजनीतिक जागरूकता का विस्तार।
18वां सत्र	1902 (28-30 दिसंबर)	अहमदाबाद	सुरेन्द्रनाथ बनर्जी	सामाजिक सुधार और शिक्षा को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श।
19वां सत्र	1903 (28-30 दिसंबर)	मद्रास	लाल मोहन घोष	भारतीय युवाओं में राष्ट्रीय भावना का विकास, सांस्कृतिक एकता पर जोर।
20वां सत्र	1904 (26-28 दिसंबर)	बंबई	सर हेनरी कॉटन	आर्थिक सुधारों और स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ावा देने की दिशा में चर्चा।

महत्वपूर्ण फ़ैक्ट :

- **1907** में **इंडियन नेशनल कांग्रेस** में **उग्रवादियों (extremists)** और **मध्यमवादियों (moderates)** के बीच मतभेदों के कारण **कांग्रेस का विभाजन** हुआ।
    - यह विभाजन **सूरत सत्र (1907)** में हुआ, जहां **लाल-बाल-पाल** (लालालाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक) के नेतृत्व में उग्रवादी समूह और **गोकुलनाथ, पेरोज़ेशाह मेहता** जैसे मध्यमवादी नेता आपस में भिन्न हो गए। इसके परिणामस्वरूप, कांग्रेस दो गुटों में बंट गई: एक उग्रवादी गुट और एक मध्यमवादी गुट।
- **ब्रुसेल्स में 1927 में हुए 'ऑपरेस्ड नेशन्स कांग्रेस'** में **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)** की ओर से **सुभाष चंद्र बोस** ने भाग लिया था। यह कांग्रेस उपनिवेशी देशों के स्वतंत्रता संग्रामों के समर्थन में आयोजित की गई थी।
- **1927 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में साइमन कमीशन** का **बहिष्कार** करने का निर्णय **कलकत्ता** में लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि उसमें भारतीय प्रतिनिधि नहीं थे, और इसे ब्रिटिश साम्राज्य की तानाशाही के रूप में देखा गया।

6 CHAPTER भारतीय आन्दोलन के चरण

प्रथम चरण (1885-1905 ई.) - नरमपंथी विचारधारा

- **ब्रिटिश शासन भारत के लिए दैवीय वरदान है।**
- भारतीय समाज जड़ है, इनमें राजनीतिक जागरूकता नहीं है, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- नरमपंथी नेताओं का ध्यान भारतीय जनता की मांगों को अभिव्यक्त करने पर था, जैसे कि ब्रिटिश शासन के प्रति अनुनय-विनय, ज्ञापन और प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना।
- इन्हें शैक्षिक विकास के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का प्रचार करना चाहिए था।

प्रमुख नरमपंथी नेता:

- दादाभाई नौरोजी
- फिरोजशाह मेहता
- गोपाल कृष्ण गोखले
- बदरुद्दीन तैयबजी
- सुरेंद्रनाथ बनर्जी
- व्योमेश चंद्र बनर्जी

द्वितीय चरण (1905-1919 ई.) - गरमपंथी युग

- **गरमपंथी नेताओं का मानना था कि ब्रिटिश शासन शोषणकारी है और भारतीयों को अधिकार मिलना चाहिए।**
- गरमपंथी नेता चाहते थे कि भारतीय समाज को राजनीतिक जागरूकता दी जाए, ताकि स्वतंत्रता की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाया जा सके।
- गरमपंथियों के आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार शामिल था।

प्रमुख गरमपंथी नेता:

- बाल गंगाधर तिलक
- लाला लाजपत राय
- विपिन चंद्र पाल
- अरविंद घोष

मुस्लिम लीग का गठन:

- अक्टूबर 1906 में आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधि दल शिमला जाकर लॉर्ड मिंटो से मिला। लॉर्ड मिंटो ने मुस्लिमों को संगठित होने का सुझाव दिया।
- 30 दिसम्बर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह ने की। इसके पहले सम्मेलन की अध्यक्षता वकार-उल-मुल्क ने की।
- 1908 में अमृतसर में आयोजित बैठक में मुस्लिम नेताओं ने पृथक निर्वाचन की मांग की।

1916 - लखनऊ अधिवेशन

- **अध्यक्ष:** अम्बिका चरण मजूमदार
- गरमपंथी और नरमपंथी नेताओं के बीच समझौता हुआ।
- कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ।
- इस समझौते के करण -
  - सूरत अधिवेशन में हुए विवाद के कारण गरमपंथी नेताओं को अलग-थलग कर दिया गया। कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य केंद्र बन गया।
  - 1907 के बाद नरमपंथी नेता निष्क्रिय हो गए थे, लेकिन समझौते के कारण नया उत्साह आया।
  - नरमपंथी ब्रिटिश नीतियों से अन्तुष्ट थे | 1909 ई. के सुधार उनके आशानुरूप नही हुआ |
  - गरमपंथी की विचारधारा मई परिवर्तन आया |
  - कट्टर नरमपंथी नेत्र फिरोजशाह एवं गोपाल कृष्ण गोखले की 1915 में मृत्यु हो गयी |
  - 1917 में कांग्रेस में पुन: फुट पड़ गई |

1909 का भारत परिषद् अधिनियम (मार्ले-मिंटो सुधार)

- केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। इसमें 69 सदस्य थे, जिनमें 9 स्थायी सदस्य और 60 अतिरिक्त सदस्य थे।
- गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य नियुक्त किया गया। **(सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय सदस्य थे जिन्हें विधि सदस्य बनाया गया)**
- प्रांतीय विधान परिषद में भी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, और उत्तर प्रदेश में 50 सदस्य थे और पंजाब, बर्मा, असम में 30 सदस्य |
- विधान परिषद के सदस्यों को विशेष मुद्दों पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया, बजट पर बहस कर सकते थे लेकिन बजट पर मत विभाजन नही करवाया जा सकता था |
- लेकिन कुछ विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती थी, जैसे विदेश नीति, देशी राज्य, रेलवे, ऋण और ब्याज।
- मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला।
- भारत परिषद में भी एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की जाएगी (भारत परिषद में पहले भी भारतीय सदस्य होते थे लेकिन अब अनिवार्य कर दिया गया था , 1907 में भारत परिषद में 2 भारतीय सदस्य थे - i. सैय्यद हुसैन बिलग्रामी ii. K.G. गुप्ता।)

दिल्ली दरबार (1911)

- ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी रानी भारत आए।

1. बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया।
2. दिल्ली को भारत की नई राजधानी घोषित किया गया।

नोट: इस समय बॉम्बे में गेटवे ऑफ़ इंडिया बनाया गया |

दिल्ली षड्यंत्र केस

- 1912 में राजधानी को दिल्ली लाने के दौरान, रास बिहारी बोस के नेतृत्व में चांदनी चौक में गवर्नर जनरल होर्डिंग II पर बम फेंका गया।
- इस घटना में चार लोगों को फांसी की सजा दी गई:
  1. अवध बिहारी
  2. अमीर चंद
  3. बालमुकुंद
  4. बसंत कुमार

कामागाटामारू हत्याकांड (1914)

- **कामागाटामारू** एक जापानी जहाज था, जिसमें सिंगापुर में रहने वाले बाबा गुरदित सिंह 376 भारतीयों को लेकर कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह गया।
- कनाडा ने इन्हें प्रवेश नहीं दिया, लेकिन भारतीयों ने इसका विरोध किया और आंदोलन किया व तटीय समिति का गठन किया | एस समिति में तीन सदस्य थे - बलवंत सिंह , रहीम हुसैन व सोहन लाल पाठक |
- जहाज जापान के यकोहामा बंदरगाह पर पहुंचा, लेकिन विश्व युद्ध के कारण ब्रिटिश सरकार ने जहाज को वापस भारत भेजने का आदेश दिया। इस दौरान कलकत्ता के बंदरगाह पर भगदड़ मच गई, जिसमें 18 लोग मारे गए थे।

होमरूल लीग आंदोलन

- यह सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के तहत आंतरिक मामलों में स्वायत्तता प्राप्त करना था।
- "इंडियन होमरूल लीग" की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में की थी।
- जबकि एनी बेसेंट ने भी सितम्बर 1916 में "हॉमरूल लीग" की स्थापना मद्रास के पास आडयार में की। उन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी का तंत्र प्रयोग किया। उनके सचिव जॉर्ज आस्थेल और वी.पी. पाड्या थे।
- तिलक के होमरूल लीग का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र (बॉम्बे को छोड़कर), आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश था, जबकि एनी बेसेंट के होमरूल लीग का कार्यक्षेत्र शेष भारत में था।
- तिलक ने 'मराठा' और 'केसरी' नामक समाचार पत्र निकाले, वहीं एनी बेसेंट ने 'New India' और 'Common Wheel' पत्र निकाले।
- सर्वाधिक शाखाएं मद्रास में थी ।
- गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ नेताओं को होमरूल लीग में प्रवेश करने से रोका।
- होमरूल लीग का संगठनात्मक स्वरूप ग्रामीण स्तर तक विस्तृत था, जहां समितियों का गठन किया गया था।
- तिलक ने स्थानीय मांगों को होमरूल के साथ जोड़ा, जिनमें निम्नलिखित शामिल थे:
  - क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन।
  - सरकारी आबकारी नीति का विरोध।
  - नमक कर का विरोध।
  - अस्पृश्यता निवारण हेतु आंदोलन।
  - सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रयास।
- **मदन मोहन मालवीय, मुहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी** जैसे नेता एनी बेसेंट के होमरूल आंदोलन के सदस्य बने थे।
- **गोखले द्वारा स्थापित 'भारत सेवक समाज' के सदस्यों पर प्रतिबंध था कि वे होमरूल लीग के सदस्य नहीं बन सकते थे।**
- जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया गया, तो सुब्रमण्यम चंद्रनाथ ने सर उपाधि त्याग दी। इससे होमरूल आंदोलन नेतृत्वविहीन हो गया।
- **20 अगस्त 1917 की मोन्टेग्यू घोषणा** के बाद, एनी बेसेंट ने होमरूल आंदोलन को समाप्त कर दिया।
- तिलक ने अपनी पुस्तक **'India Unrest'** के लेखक **विलियम वेलेटाइन शिरोल** के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने लंदन चले गये। इसके बाद, होमरूल लीग नेतृत्वविहीन हो गई।

राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण - गांधी युग (1919-1947)

चम्पारण सत्याग्रह (1917)

- चम्पारण (बिहार) के किसान तिनकठिया प्रथा से पीड़ित थे। इस प्रथा के तहत उन्हें अपनी ज़मीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, क्योंकि नील व्यापारियों ने अतिरिक्त धनराशि देकर किसानों से इस संबंध में समझौता किया था।
- किसानों के लिए नील की खेती लाभकारी नहीं थी, इसलिए वे इसके प्रति अनिच्छुक थे और इसे छोड़ना चाहते थे। इस पर तनाव बढ़ गया और एक स्थानीय नेता, राजकुमार शुक्ल ने गांधीजी को यहां आमंत्रित किया।
- गांधीजी के आगमन पर आंदोलन लोकप्रिय हुआ और सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, जिसके सिफारिशों के बाद नील की खेती को रोक दिया गया। इस प्रकार, गांधीजी का यह पहला सत्याग्रह सफल रहा।

गांधीजी के अन्य सहयोगी:

1. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
2. जे.बी. कृपलानी
3. नरहरी पारेख
4. महादेव देसाई उर्फ भाऊ

- जूडिथ ब्राउन ने अपनी पुस्तक 'Gandhi's Rise to Power' में लिखा है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन की सफलता पर गांधीजी को 'महात्मा' कहा।

खेडा आंदोलन (1918)

- खेडा (गुजरात) के किसान भारी बारिश और अकाल के कारण लगान अदा करने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने सरकार से लगान माफी की अपील की, लेकिन सरकार ने माफी नहीं दी।
- इसके बाद किसानों ने आंदोलन शुरू किया और गांधीजी की अध्यक्षता में 'गुजरात किसान सभा' का गठन किया।

प्रमुख नेता:

1. वल्लभभाई पटेल
2. इंदुलाल याग्निक
3. शंकरलाल बैंकर

अहमदाबाद मिल-मजदूर आंदोलन (1918)

- प्लेग बोनस के कारण यह आंदोलन चला था। मिल मालिक आम्बालाल हरिभाई गांधीजी के मित्र थे।
- इस आंदोलन के कारण गांधीजी ने भारत में पहली बार आमरण अनशन किया। इस आंदोलन में भी गांधीजी को सफलता मिली और मिल मालिक को 35 प्रतिशत बोनस देने पर मजबूर होना पड़ा।
- **अनुसुइया बेन** - गांधीजी की शिष्या और आम्बालाल हरिभाई की बहन थी।

रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह

- 1917 में ब्रिटिश सरकार ने सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में 'सेडिसन समिति' का गठन किया।
- विधान परिषद के भारतीय सदस्य इसके विरोध में थे, फिर भी मार्च 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया। यह कानून बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के था।
- गांधीजी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह सभा का आयोजन किया।
- 30 मार्च को अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया। हालांकि यह आंदोलन 6 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया।

6 अप्रैल, 1919 - प्रथम अखिल भारतीय हड़ताल

- स्वामी श्रद्धानंद ने गांधीजी को दिल्ली आमंत्रित किया, लेकिन गांधीजी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर बॉम्बे भेज दिया गया।
- अमृतसर में गांधीजी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे डॉ. सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को 10 अप्रैल, 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया।
- इसके विरोध में जनता के मौन जुलूस पर पुलिस ने दमनात्मक कार्रवाई की और अमृतसर में 5 लोगों की हत्या कर दी। स्थिति बिगड़ने पर मार्शल लॉ लागू किया गया और जनरल आर. डायर को कार्रवाई करने की अनुमति दी गई।

जलियांवाला बाग हत्याकांड (13 अप्रैल, 1919)

- 13 अप्रैल, 1919 को वैशाखी के दिन, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में जमा लोगों पर गोलियां चलवाईं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 379 लोग मारे गए, लेकिन वास्तविक संख्या 1000 से अधिक थी।
- हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर की मदद की थी।
- पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जनरल डायर की कार्रवाई को उचित ठहराया।
- रवींद्रनाथ ठाकुर ने इसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया।
- सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया, जिसमें 3 भारतीय सदस्य थे:
  1. चिमनलाल सीतलवाड़
  2. सुल्तान अहमद
  3. जगत नारायण
- कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर को निर्दोष ठहराया और कहा कि वह केवल परिस्थितियों को समझ नहीं पाया था।
- गांधीजी ने हंटर कमेटी की रिपोर्ट को "पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज लीपापोती" कहा।
- कांग्रेस ने हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसमें गांधीजी और मोतीलाल नेहरू भी सदस्य थे।
- हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जनरल डायर को "स्वॉर्ड ऑफ़ ऑनर" भेंट किया और उसे ब्रिटिश साम्राज्य का सम्मानित सदस्य बताया।
- कालांतर में शहीद उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी।

खिलाफत आंदोलन (1919-1921)

- मुस्लिम लीग के मध्यमवर्गीय नेतृत्व ने भारत में खिलाफत आंदोलन की नींव रखी। इसके मुख्य नेता थे:
  1. डॉ. अहमद अंसारी
  2. मौलाना मोहम्मद अली
  3. मौलाना शौकत अली
  4. अब्दुल कलाम आजाद
- इनकी मांग थी कि तुर्की का खलीफा (सुल्तान) मुस्लिमों का धार्मिक और राजनीतिक नेता है, और ब्रिटिश सरकार को तुर्की के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तुर्की ने पहले विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया था।
- 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और गांधीजी को इसका अध्यक्ष चुना गया।
- मुस्लिम लीग के जिन्ना के नेतृत्व वाले अभिजात्य वर्ग ने इस आंदोलन का विरोध किया।
- 17 अक्टूबर 1919: खिलाफत दिवस मनाया गया।
- 23 नवम्बर 1919: दिल्ली में पहला अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गांधीजी ने की।
- 20 जून 1920: इलाहाबाद में हिंदू-मुस्लिम नेताओं ने संयुक्त बैठक की और असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया।
- बाद में, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गए।
- तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में यंग तुर्क मूवमेंट चला और इन्होने खलीफा की सत्ता को समाप्त कर दिया |
- जिसने खिलाफत आंदोलन का अंत किया।

1919 का भारत सरकार अधिनियम (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार)

मोंटेग्यू की घोषणा: 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव लॉर्ड मोंटेग्यू ने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ:

- भारत परिषद् के सदस्यों की संख्या 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई।
- गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद् में 3/8 सदस्य भारतीय होंगे।
- केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की होगी:
  - काउन्सिल ऑफ स्टेट
  - केंद्र में द्विसदनात्मक असेम्बली
- केंद्र एवं प्रांतों के बीच विषयों का विभाजन किया गया:
  - संघीय सूची
  - प्रांतीय सूची
- पहली बार प्रत्यक्ष की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया।
- मुसलमानों के साथ सिक्खों, आंग्ल - भारतीय, भारतीय ईसाईयों एवं यूरोपियन्स के लिए भी पृथक निर्वाचन पद्धति लागू कर दी गई |
- प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना: इसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को दो श्रेणियों में बांटा गया:
  - आरक्षित (Reserved)
  - स्थानांतरित (Transferred)
- 1909 के अधिनियम में कहा गया था कि 10 वर्षों में भारत के नए सुधार लागू किए जाएंगे।

Note: सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने 1919 में "अखिल भारतीय उदारवादी संघ" का गठन किया।

असहयोग आंदोलन (1920–1922)

- सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन (अध्यक्ष - लाला लाजपत राय) में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। कुछ नेताओं ने विरोध किया, जैसे - सी.आर. दास, मदन मोहन मालवीय, जिन्ना, एनी बेसेंट, शंकरन नायर, विपिचंद्र पाल।
- फिर भी गांधी जी ने अली बंधुओं एवं मोतीलाल नेहरू के समर्थन से यह प्रस्ताव पारित करवा लिया |
- बाद में दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन (अध्यक्ष - सी. वाय. चिंतामणि) में आंदोलन को औपचारिक रूप से स्वीकृति दी गई।
- जब असहयोग का प्रस्ताव पास हुआ तो इसके विरोध में जिन्ना, एनी बेसेंट एवं विपिन चन्द्र पल ने कांग्रेस छोड़ दी ।
- विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई।

नागपुर अधिवेशन का ऐतिहासिक महत्व इस कारण है कि इसमें यह स्वीकार किया गया कि स्वराज्य प्राप्ति के लिए सरकार का शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक विरोध ही एकमात्र मार्ग होगा।"

चौरी-चौरा कांड (1922)

- **तारीख:** 4 फरवरी 1922
- **स्थान:** चौरी-चौरा, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)
- **घटना:** पुलिस फायरिंग से गुस्साए आंदोलनकारियों ने थाना जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए।
- इस हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने 22 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया।

स्वराज पार्टी (1923)

- **1 जनवरी 1923** को **इलाहाबाद** में **स्वराज पार्टी** की स्थापना की गई।
- **अध्यक्ष** – चित्तरंजन दास
- **सचिव** – मोतीलाल नेहरू
- **1923 के चुनावों** में स्वराज दल ने शानदार प्रदर्शन किया:
  - **मध्य प्रांत** में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया।
  - **बंगाल, संयुक्त प्रांत और बॉम्बे** में प्रमुखता से जीत दर्ज की।
  - **केन्द्रीय विधानमंडल** में कुल **101 में से 42 सीटें** हासिल कीं।
- इस सफलता के परिणामस्वरूप, स्वराज पार्टी ने **विठ्ठलभाई पटेल** को **केन्द्रीय विधान परिषद** का अध्यक्ष निर्वाचित करवाने में सफलता प्राप्त की।

स्वराज पार्टी को **"परिवर्तनवादी"** कहा गया क्योंकि इसके नेता **विधानमंडल में प्रवेश कर सरकार के अंदर रहकर विरोध और जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाना चाहते थे**।

साइमन कमीशन (1927)

- 1927 ई. में **साइमन कमीशन** का गठन किया गया, जिसमें **7 ब्रिटिश सदस्य** थे। इसका उद्देश्य भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए सिफारिशें देना था क्योंकि 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान था कि प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात ब्रिटिश सरकार एक आयोग का गठन करेगी जो संवैधानिक सुधारों की सिफारिश करेगा।
- इसके विरोध में नेहरू जी ने **सात सदस्यीय समिति** बनाई, जिसने अपनी रिपोर्ट **10 अगस्त 1928** को प्रस्तुत की।
- चूंकि **साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था**, इसलिए भारतीयों ने इसका तीव्र विरोध किया।
- हालांकि **मद्रास की जस्टिस पार्टी**, **पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी**, **डॉ. भीमराव अंबेडकर**, तथा **मुस्लिम लीग का शफी गुट**—इन सभी ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया।

साइमन कमीशन की सिफारिशें:

- 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत लागू की गई **द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त** कर और उत्तरदायी शासन की स्थापना की जायेगी |
- भारत में **संघात्मक व्यवस्था** लागू की जायेगी ।
- केंद्र में भारतीयों को कोई भी उत्तरदायित्व न दिया जाए।

- ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों को मिलाकर एक **ब्रिटिश संघ** का गठन किया जाए।
- **बर्मा को भारत से अलग** किया जाए, तथा उड़ीसा और सिंध को अलग प्रांतों का दर्जा दिया जाए।
- **मताधिकार को अधिक व्यापक** किया जाए, यद्यपि सार्वभौमिक मताधिकार न दिया जाए।
- **पृथक निर्वाचन प्रणाली** को असंतोषजनक बताया गया, फिर भी उसे जारी रखने की सिफारिश की गई।

नेहरू रिपोर्ट (1928)

- **साइमन कमीशन के बहिष्कार** के बाद भारत सचिव **लॉर्ड बर्कन हेड** ने भारतीयों के समक्ष चुनौती राखी कि वे एक ऐसा संविधान बनाकर ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करें जिसे सभी दलों का समर्थन प्राप्त हो।
- कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार कर **28 फरवरी 1928 को दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन** बुलाया और **मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति** का गठन किया।

नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशें:

1. ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों को मिलाकर एक **संघीय ढांचे** की स्थापना की जाए।
2. **पृथक निर्वाचन प्रणाली समाप्त** की जाए, परंतु जहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, वहां उन्हें **आरक्षण** दिया जाए।
3. **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार** की मांग की गई।
4. **दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों** के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं।
5. भारत में **सर्वोच्च न्यायालय** की स्थापना हो और इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में अपील भेजना बंद किया जाए।
6. **बर्मा को भारत से अलग** किया जाए।
7. भारत को **डोमिनियन स्टेट** का दर्जा दिया जाए।
8. **सिंध, उड़ीसा और उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत** को नए प्रांत के रूप में गठित किया जाए।
9. **भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन** किया जाए।

- **मुस्लिम लीग**, **हिंदू महासभा**, और **सिख महासभा** ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया।
- **जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस** ने डोमिनियन स्टेट की मांग का विरोध किया और **इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग** की स्थापना की।
- नेहरू रिपोर्ट के विरोध में **मोहम्मद अली जिन्ना** ने **14 सूत्रीय मांग-पत्र** प्रस्तुत किया जिसमें **अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों को देने** की बात शामिल थी।

लाहौर अधिवेशन (1929)

अध्यक्ष – जवाहरलाल नेहरू

- अधिवेशन में **'पूर्ण स्वराज'** का प्रस्ताव पारित किया गया।
- 26 जनवरी को **स्वतंत्रता दिवस** के रूप में मनाने की घोषणा की गई।
- कांग्रेस कार्यसमिति को **सविनय अवज्ञा आंदोलन** शुरू करने की स्वीकृति दी।
- **गांधीजी ने 11 सूत्रीय मांग-पत्र** प्रस्तुत किया।
- मांगें न माने जाने पर **12 मार्च 1930 को गांधीजी ने साबरमती आश्रम से 78 साथियों के साथ दांडी यात्रा** शुरू की और **6 अप्रैल 1930** को दांडी पहुंचकर **नमक कानून तोड़ा**, जिसे **दांडी मार्च** कहा गया – यही से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई।

गांधी-इरविन समझौता (1931)

5 मार्च 1931 को तेजबहादुर सप्रू और जयकर के प्रयासों से यह समझौता हुआ, जिसके तहत:

- **हिंसा अपराधियों के अतिरिक्त का दोषी नहीं ठहराए गए सभी राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई**;
- अपहरण की सम्पत्ति वापस कर दी जायेगी।**अभी तक वसूल नहीं किए गए सभी जुर्मानों को माफ करना**;
- उन सभी जमीनों को वापस करना जो अभी तक तीसरे पक्ष को नहीं बेची गई हैं;
- उन सरकारी कर्मचारियों के साथ उदारता बरती जाए जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था;
- तटीय गांवों में व्यक्तिगत उपयोग (बिक्री के लिए नहीं) के लिए नमक बनाने का अधिकार;
- शांतिपूर्ण और गैर-आक्रामक धरना देने का अधिकार;
- अध्यादेशों को वापस लेना।
- वायसराय ने गांधी की **दो मांगों को ठुकरा दिया -**
  - **पुलिस ज्यादतियों की सार्वजनिक जांच**,
  - **भगत सिंह और उनके साथियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलना।**
- कांग्रेस की ओर से गांधी**जी ने इस पर सहमति व्यक्त की -**
  - **सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना।**
  - **संवैधानिक मुद्दे पर अगले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना।**
  - **गांधी**-इरविन सम**झौते के बाद**, **गांधीजी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया।**

गोलमेज सम्मेलन (1930–1932)

- ब्रिटिश सरकार द्वारा **तीन गोलमेज सम्मेलन** आयोजित किए गए (1930, 1931, 1932) ।
- कांग्रेस ने केवल **दूसरे गोलमेज सम्मेलन (1931)** में भाग लिया।
- कांग्रेस की ओर से केवल **गांधीजी** ने भाग लिया।
- गांधीजी **'राजपूताना' नामक जहाज** से लंदन गए थे।
- **सरोजिनी नायडू** और **मदन मोहन मालवीय** ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया।
- **फ्रैंक मोरेस** ने गांधीजी की लंदन यात्रा का वर्णन किया।
- गांधीजी 28 दिसंबर, 1931 को खाली हाथ भारत लौट आए।
- लंदन से लौटकर गांधीजी ने **सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू** किया (1932) ।
- अंततः **1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त** कर दिया गया।

कराची अधिवेशन (1931)

- **6 अप्रैल 1930** को गांधीजी ने दांडी में नमक कानून का उल्लंघन किया था।
- 1930–31 में **बच्चों के लिए 'वानर सेना'** और **लड़कियों के लिए 'मंजरी सेना'** का गठन किया गया।
- **अध्यक्ष:** सरदार वल्लभभाई पटेल
  - **गांधी-इरविन समझौते** (दिल्ली समझौता) को स्वीकृति दी गई।
  - कांग्रेस के **आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा** की गई, जिसमें अर्थव्यवस्था के समाजवादी ढांचे को अपनाने पर बल दिया गया।

सांप्रदायिक पंचाट (16 अगस्त 1932)

- 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री **रामसे मैकडोनाल्ड** द्वारा यह घोषणा की गई कि **दलितों को पृथक निर्वाचित प्रतिनिधित्व** प्रदान किया जाएगा।
- इस **पंचाट** ने दलित वर्गों सहित अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल और आरक्षित सीटों (78 आरक्षित सीटें) का प्रावधान किया।
- उस समय गांधीजी **यरवदा जेल** में थे। उन्होंने **20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन** शुरू कर दिया।

पूना समझौता (26 सितंबर 1932)

- यह समझौता 26 सितम्बर 1932 को **महात्मा गांधी** और **डॉ. भीमराव अंबेडकर** के बीच हुआ।
- **राजेन्द्र प्रसाद, सी. राजगोपालाचारी** और **पुरुषोत्तमदास टंडन** ने इस समझौते को कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- डॉ. अंबेडकर ने **पृथक निर्वाचन प्रणाली** को त्याग दिया और **सामान्य निर्वाचन में आरक्षण** स्वीकार किया। दलितों के लिए सीटें **71 से बढ़ाकर 148** कर दी गईं।
- गांधीजी ने **दलितों को 'हरिजन'** नाम दिया, **'हरिजन' नामक पत्रिका** शुरू की और **अखिल भारतीय हरिजन संघ** की स्थापना की।

भारत सरकार अधिनियम 1935

प्रमुख प्रावधान:

1. **भारत परिषद** को समाप्त कर उसके स्थान पर एक **सलाहकार समिति** का गठन किया गया।
2. **संघीय ढांचे की परिकल्पना** की गई, जिसमें **ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों** को शामिल किया जाना था। रियासतों की रुचि न होने के कारण यह संघ अस्तित्व में नहीं आ सका।
3. केंद्र में **द्विसदनीय विधायिका** की स्थापना की गई:

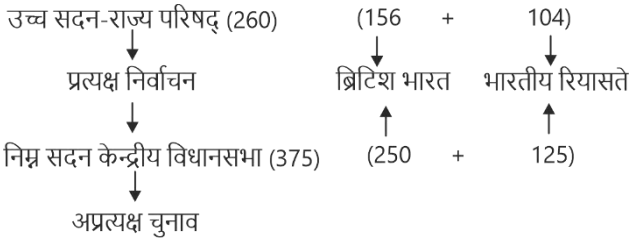

4. केंद्र में **द्वैध शासन प्रणाली** लागू की गई; विषयों को दो भागों में बाँटा गया:
   - आरक्षित विषय
   - हस्तांतरित विषय
5. **बर्मा को भारत से अलग** कर दिया गया।
6. **मुस्लिम, सिख और एंग्लो-इंडियन समुदायों** के लिए **पृथक निर्वाचनों** की व्यवस्था जारी रखी गई।
7. **उड़ीसा, सिंध और उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत** नए प्रांत बनाए गए।
8. विषयों को तीन सूचियों में विभाजित किया गया:
   - संघ सूची
   - राज्य सूची
   - समवर्ती सूची
9. गवर्नर जनरल को **वीटो और अध्यादेश** जारी करने का अधिकार दिया गया।
10. **प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन समाप्त** कर **उत्तरदायी शासन** की स्थापना की गई और **प्रांतीय स्वायत्तता** पर बल दिया गया।
11. **दलितों को आरक्षण** प्रदान किया गया।
12. **संघीय न्यायालय** की स्थापना की गई।
13. **RBI** की स्थापना की गई।
14. **मताधिकार का दायरा बढ़ाया गया**; महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया।
15. **संघीय लोक सेवा आयोग** का गठन किया गया।

1937 के प्रांतीय चुनाव

- **भारत सरकार अधिनियम 1935** के तहत प्रांतों में चुनाव कराए गए।
- कुल 11 प्रांतों में से **5 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत** मिला: बिहार, मद्रास, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत।
- **बॉम्बे में कांग्रेस एक सीट से बहुमत से पीछे रह गई।**
- **उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत और असम** में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी।
- **सिंध, पंजाब और बंगाल** में कांग्रेस पिछड़ गई।
- **मुस्लिम लीग** को किसी भी प्रांत में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला।
- लीग ने विभिन्न प्रांतों में गठबंधन सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया।
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान **ब्रिटिश सरकार ने भारत को युद्ध में शामिल करने की घोषणा** की, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया।
- **15 नवम्बर 1939 को कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा** दे दिया।
- **22 दिसम्बर 1939** को **मुस्लिम लीग ने 'मुक्ति दिवस'** मनाया।